

THE
PARLIAMENTARY DEBATES

OFFICIAL REPORT

IN THE HUNDRED AND THIRTY-SEVENTH SESSION OF THE RAJYA SABHA

Commencing on the 20th February, 1986/1st Phalgun, 1907 (Saka)

I

2

RAJYA SABHA

*Thursday, the 20th February, 1986/
1st Phalgun, 1907 (Saka)*

The House met at one of the clock,
Mr. Chairman in the Chair.

MEMBER SWORN

Shri Sagar Rayka (Gujarat)

**PRESIDENT'S ADDRESS—Laid
on the table**

SECRETARY-GENERAL: Sir,
I beg to lay on the Table a copy (in
English and Hindi) of the President's
Address to both the Houses of Parlia-
ment assembled together on the 20th
February, 1986 [Placed in Library. See
No. LT-1947/86]

**[Text of the President's
Address in Hindi]**

माननीय सदस्यगण,

1986 में संसद् के इस पहले अधिवेशन
में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी
प्रसन्नता हो रही है। मैं नये सदस्यों को
बधाई देता हूँ।

2. पिछले साल संसद् ने अपनी कार्यवाही
उद्देश्यपूर्ण ढंग से और सहयोग के वाता-
वरण में चलाई। आपके सामने जो
बजट और विधान कार्य हैं उनको सफलता

के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको
अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

3. जुलाई, 1985 में सरकार ने पंजाब
में जटिल और कठिन समस्याओं को
सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम
उठाया। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि
एकता और अखण्डता की ताकतों को
मजबूत किया जाए। सर्वोच्च राष्ट्रीय
हित को ध्यान में रख कर नीति निर्धारित
की गई। आतंकवाद पर लोकतंत्रीय
प्रणाली की जीत हुई। पंजाब में शांति-
पूर्ण चुनावों ने इस बात को सिद्ध कर
दिया कि राज्य में बहुत बड़ी संख्या में
लोग अमन-चैन और सामान्य स्थिति कायम
करने के इच्छुक हैं।

4. जिन लोगों को जनादेश मिला है
उनके ऊपर भारी ज़िम्मेदारी है। उनका
सबसे पहला काम यह है कि वे ऐसे लोगों
को अलग-थलग कर दें जो साम्प्रदायिक
सद्भावना और शांति को भंग करने के
लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। इस
काम में उन्हें उन सभी राजनीतिक ताकतों
का समर्थन मिलेगा जो भारत की एकता
और अखण्डता के लिए वचनबद्ध हैं। विघटन-
कारी ताकतों के साथ किसी भी हालत
में समझौता नहीं किया जा सकता और
न ही किया जाना चाहिए। यह जरूरी
है कि सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक
ताकतें, हमारे संविधान में शामिल राष्ट्रीयता,
धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाज-
वाद के उन मूल्यों की, जो भारत की

एकता के आधार हैं, रक्षा के लिए मिलकर एक जन-अभियान चलाएं।

5. असम समझौते के बाद वहां विधान सभा और लोक सभा के चुनाव हुए। वहां एक नई सरकार ने कार्यभार सम्भाला है।

6. सरकार पंजाब और असम समझौतों को पूरी तरह लागू करने के लिए वचनबद्ध है।

7. सरकार उन सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करती है जिनकी देश के विभिन्न भागों में हुई हिंसात्मक घटनाओं में जाने गईं या जो लोग घायल हुए या जिनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा। सार्वजनिक जीवन में हिंसा हमारी सभ्यता की प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। एक वर्ग या दूसरे वर्ग द्वारा समझी जाने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए हिंसा का बार-बार सहारा लेने से उन लोगों को गहरी तकलीफ होनी चाहिए जो लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था रखते हैं। हालांकि, सरकार को जहां कहीं भी हिंसा हो उसे सख्ती से दबाना चाहिए लेकिन यह जरूरी है कि जो राजनीतिक दल लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था रखते हैं, उन्हें लोगों के बीच जाकर अपने लगातार और उद्देश्यपूर्ण कार्यों के जरिये हिंसा के मूल कारणों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। साम्प्रदायिक और दूसरी प्रकार की हिंसा से छोटे-मोटे लाभ हासिल करने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए।

8. साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय एकता के लिए गम्भीर खतरा बनी हुई है। धार्मिक रूढ़िवाद और कट्टरपन से यह खतरा और बढ़ता जा रहा है। ये प्रवृत्तियां प्रतिक्रियावाद सामाजिक दृष्टिकोण की प्रतीक हैं, जो निहित स्वार्थों के विरुद्ध गरीबों और शोषितों के संघर्ष को कमजोर करती हैं। धर्म-निरपेक्षता को मजबूत करने के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद को दृढ़ निश्चय के साथ व्यवस्थित रूप में कार्य करना होगा।

9. मैंने अपने 17 जनवरी, 1985 के भाषण में सरकार की प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा पेश की थी। मैं मुख्य बातों को संक्षेप में दोहरा रहा हूं:-

- (i) एक स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के प्रति वचनबद्धता ;
- (ii) प्रशासनिक सुधार ;
- (iii) न्यायिक सुधार ;
- (iv) एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ;
- (v) महिलाओं के लिए एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम ;
- (vi) राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ावा देने और श्रेष्ठता हासिल करने के कार्यक्रमों में युवकों को शामिल किया जाना ;
- (vii) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना ;
- (viii) केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना ;
- (ix) एक नई कपडा नीति ; और
- (x) औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा के उपायों की पूरी जांच।

10. मेरी सरकार ने पिछले साल के लिए जो कार्य निर्धारित किए थे वे बहुत हद तक पूरे कर लिए हैं।

11. दल-बदल विरोधी अधिनियम अब विधि पुस्तक में शामिल है। कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को अंशदान दिए जाने को कानूनी स्वीकृति मिल गई है। सरकार ने सार्वजनिक जीवन में एक नया वातावरण कायम करने की कोशिश की है। इससे राष्ट्रीय विश्वास को शक्ति मिली है। सभी वर्ग के लोगों में सार्वजनिक मामलों में हिस्सा लेने की गहरी भावना और भारी उत्साह पाया गया जो पिछले साल की एक विशेषता रही। इन्हीं गुणों के आधार पर हमें सार्वजनिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना है।

12. भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने के लिए

कई कदम उठाए गए हैं। सभी स्तरों पर ठोस कार्मिक प्रवृद्ध और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर काफी जोर दिया गया है। सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने की उचित व्यवस्था मौजूद है। इसके परिणामों का लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के लागू किए जाने पर निगाह रखने के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना की गई है। सरकार के सभी विभागों को हिदायत दी गई है कि वे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विस्तृत कार्य योजनाएं बनाएं। इन्हीं के आधार पर उनकी प्रगति को आंका जाएगा। प्रशासनिक सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। इस प्रणाली को और अच्छा बनाने पर गहराई से विचार हो रहे हैं, ताकि निर्णय जल्दी लिए जा सकें और उन्हें बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।

13. सरकार का न्याय प्रक्रिया में लगने वाली देरी को खत्म करने का पक्का इरादा है। लोक अदालतों के तजुबों से यह सिद्ध हो चुका है कि हमारी न्याय प्रणाली की बुराई को दूर करने के लिए एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों की स्थापना से अदालतों का भार हल्का होगा। इससे वे बकाया मामलों के निबटाने में अधिक समय दे सकेंगे। हालांकि ये उपाय स्वागत योग्य हैं, फिर भी ये न्याय को कम खर्चीला बनाने और न्याय को आसानी से गरीबों की पहुंच तक लाने की बुनियादी समस्या के समाधान के लिए काफी नहीं है। इसके लिए आमूल परिवर्तनों की आवश्यकता है। सरकार ने विधि आयोग को ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

14. सरकार ने अगस्त, 1985 में 'शिक्षा की चुनौती' नाम से एक दस्तावेज प्रकाशित किया। इसका उद्देश्य था विभिन्न विषयों और विकल्पों पर व्यापक और गहन राष्ट्रीय बहस के लिए लोगों को प्रेरणा देना। सरकार को इस बात पर संतोष है कि इस बहस में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए हैं और कई उपयोगी विचार और उपाय सामने आए हैं। नई शिक्षा नीति का मसौदा जल्दी ही संसद में पेश किया जाएगा।

15. सरकार ने महिलाओं को उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की है। महिलाओं के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य होगा—एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र के विकास में महिलाओं को अपनी भूमिका पूरी तरह निभाने के योग्य बनाना।

16. युवा विकास के कार्यक्रमों में काफी प्रगति हुई है, परन्तु अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना है।

17. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना हो चुकी है और इसने वन लगाने के महान कार्य को शुरू कर दिया है। हाल ही की एक बैठक में सभी राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय भूमि प्रयोग नीति और बंजर भूमि विकास की नीतियों के प्रति एक सम्मिलित रवैया अपनाने की अपना समर्थन दिया है।

18. केन्द्रीय गंगा में प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई है। संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से गंगा के प्रदूषण को रोकने का काम पूरे जोर-शोर से शुरू हो गया है।

19. जून, 1985 में एक नई कपड़ा नीति की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों के लिये सस्ते कपड़े का उत्पादन करना है। इस नीति का उतना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा करना भी है। यह विचार है कि सातवीं योजना में 70 करोड़ वर्ग मीटर कंट्रोल तथा जनता कपड़े के संपूर्ण उत्पादन को हथकरघा क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। दि हैण्डलूमस (रिजर्वेशन आफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन) एक्ट, 1985 को पास कर दिया गया है, ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को जो करोड़ों लोगों की रोजी का जरिया है, मजबूत बनाया जा सके। इस नीति को पूरी तरह और कुशलता के साथ लागू करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

20. सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा और खतरनाक पदार्थों के प्रबंध से संबंधित मामलों की जांच पूरी करली है और संसद के इस अधिवेशन में इस पर विधेयक लाया जायेगा।

21. सांस्कृतिक समरसता की भावना को बढ़ावा देने के लिये सरकार सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करेगी जिनमें से अभी तक तीन स्थापित किये जा चुके हैं। ये केन्द्र प्रादेशिक और भाषाई सीमाओं से ऊपर उठकर हमारी विविध समृद्ध क्षेत्रीय सांस्कृतिक परम्पराओं और उनमें निहित एकता को प्रस्तुत करेंगे। ये हमारी संस्कृति के श्रेष्ठ गुणों को जन साधारण तक पहुंचावेंगे और उनके जीवन और संघर्षों के साथ उनका समन्वय स्थापित करेंगे। उपनिवेशक काल में जनता और भारतीय संस्कृति को जीवित परम्पराओं के बीच खड़ी की गई दीवार को तोड़ना होगा। साथ ही इन केन्द्रों का उद्देश्य लोककला को नई शक्ति प्रदान करना होगा, जिससे हमारे देश के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाया है।

22. अब मैं अपनी अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख प्रवृत्तियों के संबंध में चर्चा करूंगा।

23. राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस योजना की बुनियादी नीति निर्धनता दूर करने और एक मजबूत, आत्मनिर्भर तथा आधुनिक अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने के दीर्घकालीन ध्येय को सामने रखकर तैयार की गई है। इसमें निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया गया है। और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की विकास क्षमता को बढ़ाने के लिये मूल क्षेत्रों में काफी मात्रा में पूंजी लगाई जाये।

24. योजना को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि हम पक्के इरादे से और पूरी तरह वचनबद्ध होकर पूंजी निवेश के लिये काफी मात्रा में साधन जुटावें। एक मजबूत, खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने के लिये अथक परिश्रम, त्याग और मुश्किलें बर्दाश्त करने की जरूरत है। विकास के मार्ग में मुद्रास्फीति रुकावट न बने, इसके लिये वचन के काफी साधन जुटाने होंगे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है

कि इन वचनों का इस्तेमाल कारगर ढंग से किया जाये। हमें चुनौती का सामना करना होगा। विकास के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।

25. निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों को जोर शोर से लागू करने के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक करोड़ पचास लाख परिवारों को सहायता पहुंचाना था। वास्तव में, इससे एक करोड़ छियासठ लाख परिवारों को फायदा हुआ, जिनमें चौसठ लाख परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे। इन कार्यक्रमों को मजबूत बनाया जा रहा है और अनाज के अतिरिक्त भंडार का उपयोग वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का विस्तार करने के लिये किया जायगा, जिससे 10 लाख अतिरिक्त परिवारों को लाभ होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों को आवास की सुविधायें देने के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक सौ करोड़ रुपये सालाना की व्यवस्था की गई है।

26. दो लाख 31 हजार गांव ऐसे थे जहां पीने का अच्छा पानी उपलब्ध नहीं था। इनसे एक लाख 92 हजार गांवों को मार्च, 1985 के अन्त तक पीने के पानी का कम से कम एक साधन अवश्य उपलब्ध कराया गया। 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम में और तेजी लाई गई।

27. वर्ष 1985-86 में कृषि के क्षेत्र में बराबर प्रगति हुई है। नवम्बर, 1985 में, सरकार के पास अनाज का भंडार 1984 की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक था। इसके फलस्वरूप सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों और दूसरे अभावग्रस्त वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों, गर्भवती माताओं, बच्चों आदि के लिये खास रियायती दामों पर गेहूं और चावल बांटने की योजना चलाई है। खरीफ की फसल के लिये निश्चित क्षेत्रों में एक व्यापक फसल बीमा योजना शुरू की गई है।

सरकार ऐसी योजनाओं का और अधिक विस्तार करने पर विचार कर रही है।

28. 1985-86 के पहले सात महीनों में औद्योगिक उत्पादन 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। सरकार की नीति के कारण पूंजी निवेश का एक उत्साहजनक वातावरण तैयार हुआ है। बुनियादी उद्योग का कार्य अच्छा रहा है। पिछले साल के पहले नौ महीनों की तुलना में बिजली का उत्पादन 8.2 प्रतिशत, विक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 12.9 प्रतिशत और उर्वरक का उत्पादन 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। हमारी बन्दरगाहों में 13.2 प्रतिशत अधिक माल लादा-उतारा गया है और रेलवे ने माल ढोने का एक नया रिकार्ड कायम किया है।

29. वर्ष 1985-86 में केन्द्रीय योजना लागत में विशेषकर निर्धनता दूर करने के कार्यक्रमों, मानव संसाधन विकास और बुनियादी उद्योगों पर 1984-85 के मुकाबले 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य योजनाओं के लागत में काफी वृद्धि की गई थी। सरकार 1985-86 में खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता पर 1650 करोड़ रुपये और उर्वरक आर्थिक सहायता पर 2050 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया गया और उपयुक्त सप्लाई प्रबंध से जरूरी चीजों की कमी नहीं होने दी गई। यह बहुत संतोष की बात है कि सार्वजनिक पूंजी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

30. कर-वसूली का काम उत्साहजनक रहा है, जिससे निराशाजनक स्थिति का अनुमान गलत साबित हुआ है। प्रत्यक्ष करों की वसूली पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है। अप्रत्यक्ष करों की वसूली में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल कर वसूली में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले दस वर्षों में सबसे ज्यादा है। कर की चोरी करने वालों, दस्करों और काला-बाजारियों के खिलाफ एक जोरदार अभियान चलाया गया था। जो कर्मचारी आर्थिक अपराधियों से मिलीभगत के दोषी पाये गये उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई-

है। सरकार आर्थिक जीवन को साफ सुथरा बनाने और काले धन की बुराई को खत्म करने का पक्का इरादा रखती है।

31. पहली बार, पंचवर्षीय योजना की अवधि तक की एक दीर्घकालीन आर्थिक नीति की घोषणा की गई है। आर्थिक नीति को एक दीर्घकालीन दिशा प्रदान की गई है। सरकार को विश्वास है कि इस नीति से अवश्य ही आर्थिक प्रगति होगी और लाभकारी निवेश तथा रोजगार के अवसरों का तेजी से विस्तार होगा।

32. सामाजिक न्याय के साथ विकास के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में अर्थ-व्यवस्था के ढाँचे संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान देना जरूरी है। सार्वजनिक पूंजी निवेश के स्तरों में लगातार वृद्धि होती रहे, इसी पर भारत का विकास निर्भर करता है। इन निवेशों के लिये धन की व्यवस्था किस प्रकार होगी? पिछली योजनाओं में बड़े पैमाने पर किये गये पूंजी निवेश से काफी लाभ मिलना चाहिये। उत्पादन लागत में कमी करनी होगी। राष्ट्रीय बचत के हर पैसे का उत्पादन में अधिक से अधिक उपयोग करना होगा नहीं तो आत्मनिर्भर विकास की गति को कायम रखने, गरीबी हटाने के कार्यक्रमों का विस्तार करने, और आर्थिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिये बड़े पैमाने पर अपेक्षित पूंजी निवेश के लिये वास्तविक साधनों को हासिल करना कठिन होगा। देर-सबेर, बल्कि जल्दी ही हमें स्थिति की असलियत का सामना करना है। किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि विकास, सामाजिक न्याय, मूल्यों में स्थिरता और आत्मनिर्भरता का बिना कार्यकुशलता, अनुशासन और जिम्मेदारी के हासिल किया जा सकता है। समकालीन इतिहास हमें ऐसे खतरों से सावधान करता है।

33. हमें उत्पादन में काम आने वाले सामान की लागत को कम करना होगा और निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में कमी करनी होगी। नहीं तो देश तथा विदेश के बाजारों में हमारा-

माल विक नहीं पायेगा। उत्पादकता के निम्न स्तरों और उत्पादन की ऊंची लागत के आधार पर एक आधुनिक औद्योगिक समाज का विकास नहीं हो सकता। अगर मौजदा औद्योगिक प्रतिष्ठान हर साल घाटे में चले, तो रोजगार के नये अवसर नहीं पैदा किये जा सकते। परिचालन कार्य में कुशलता न होने से उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और इसका असर अवश्य ही कीमतों पर होता है, जिससे जनता पर बोझ पड़ता है। इससे हर तरफ कीमतों में वृद्धि होती है और वास्तविक निवेश में कमी हो जाती है।

34. योजना की प्रक्रिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी क्षमता से कठिन प्रश्नों का सामना करते हैं और सख्त निर्णय लेते हैं। इन निर्णयों में त्याग निहित है, परन्तु इनके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। निर्धन लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिये विकास निहायत जरूरी है। क्या हम ऐसे निर्णयों को टाल सकते हैं, जिनसे विकास की यह प्रक्रिया सुरक्षित और मजबूत हों? राष्ट्रों का निर्माण ऐसी पीढ़ियों द्वारा किया जाता है जो एक सुन्दर भविष्य के लिये त्याग करती हैं।

35. भुगतान शेष की स्थिति से इसी प्रकार की चुनौती उत्पन्न होती है। 1985-86 में हमारे निर्यात में मंदी रही है और हमारा आयात बढ़ा है। पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य तेलों का आयात देश की क्षमता से काफी अधिक हुआ है। मूल प्रश्न यह है कि क्या हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं या नहीं। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती खपत को रोकना होगा और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। हमें अपने पूंजीगत माल के आयात पर भी नये सिरे से गौर करना होगा। हम नई टेक्नालोजी को रोकना नहीं चाहते, क्योंकि इससे हमें नुकसान होगा। परन्तु हमें यह देखना है कि ऐसी टेक्नालोजी जरूरत के कठिन मापदंड की पूर्ति करे। बाहर से वित्तीय साधनों की जरूरत है, किन्तु सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि भारत कभी भी

विदेशी बैंकों और संस्थाओं की दया पर निर्भर न रहे। हमारे विकास के सिद्धांत का केन्द्र बिन्दु आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता है। हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखने के लिये हर कीमत चुकायेंगे।

36. गुटनिरपेक्षता, शांति और परमाणु निःशस्त्रीकरण हमारी विदेश नीति के बुनियादी उद्देश्य बने हुये हैं। इनसे दोस्ती और सहयोग के क्षेत्र का विस्तार होगा और एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण में मदद मिलेगी।

37. सोवियत संघ और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय बातचीत शुरू हुई, हम इसका स्वागत करते हैं। यह जरूरी है कि परमाणु शस्त्रों की होड़ को रोकने और परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पाबन्दी लगाने की व्यापक संधि के लिये कदम उठाये जायें। छह राष्ट्रों द्वारा इस सम्बन्ध में पहल की गई है। जनवरी, 1985 में दिल्ली में की गई घोषणा का सारे संसार के जनमत पर अच्छा असर पड़ा है। छह राष्ट्रों के नेता अगले कदमों के बारे में एक दूसरे से संपर्क बनाये हुये हैं।

38. पिछले वर्ष में उप-महाद्वीप के वातावरण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हमने अनेक क्षेत्रों में अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में प्रगति की है। परन्तु हम श्रीलंका में जातीय समस्या से उत्पन्न स्थिति और पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों की क्षमता हासिल करने की लगातार कोशिशों से चिंतित हैं। हम यह मानते हैं कि श्रीलंका की स्थिति केवल राजनीतिक आधार पर ही हल की जा सकती है, सैनिक हल ढूँढने की कोशिशें असफल रहेंगी और इसका परिणाम यह होगा कि बहुत बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा।

39. ढाका में दिसम्बर, 1985 में हुई दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संस्था (सार्क) की स्थापना का सरकार स्वागत करती है। हम आशा करते हैं कि इससे हमारे क्षेत्र में दोस्ती और सहयोग की शक्तियों को बल मिलेगा।

40. सरकार ने तनाव के मुख्य क्षेत्रों को कम करने के लिये अथक प्रयास

किये हैं। अक्टूबर में बहामा में हुई राष्ट्र-मंडल देशों की बैठक में, जिसमें हमारे प्रधान मंत्री ने भाग लिया था, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीका के संबंध में राष्ट्रमंडल समझौते के स्वीकार किये जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति पर चलने वाली सरकार के विरुद्ध पूर्ण अधिदेशात्मक प्रतिबंधों की लगातार मांग कर रहे हैं। यदि वहां की सरकार, तथा वे सरकारें जो दक्षिण अफ्रीकी सरकार को समझाने की स्थिति में हैं, समय रहते कार्य नहीं करेंगी तो वहां बड़े पैमाने पर हिंसा को टाला नहीं जा सकेगा।

41. प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं वर्षगांठ में भी भाग लिया। राष्ट्रमंडल देशों के नेताओं द्वारा विश्व व्यवस्था के संबंध में स्वीकार की गई नसाऊ घोषणा में अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता और संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाने का जोरदार समर्थन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का समर्थन करना हमारी विदेश नीति का एक मुख्य अंग है। हम बहुपक्षीय संस्थाओं के लिये बढ़ते हुये खतरे तथा एक पक्षीय कार्यवाही का सहारा लेने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से चिन्तित हैं। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कोशिशों का समर्थन करती है और साथ ही उपनिवेशिक शासन के अधीन लोगों को अपने न्यायपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सभी साधनों का इस्तेमाल करने के अधिकारों को मान्यता देती है।

42. सरकार को इस बात पर खेद है कि फिलीस्तीनी लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है जिनमें उनका अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिकार भी शामिल है। जब तक इस बुनियादी समस्या को हल नहीं किया जाता पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित नहीं होगी।

43. प्रधान मंत्री ने सोवियत संघ, मिश्र, फ्रांस, अल्जीरिया, अमेरिका, भूटान, ब्रिटेन, क्यूबा, नीदरलैंड्स, वियतनाम, जापान, ओमान तथा मालदीव की सरकारों यात्रा की। प्रधान मंत्री की सोवियत नेताओं से मोस्को में बातचीत से सोवियत संघ के साथ

हमारे परम्परागत गहरे मैत्री संबंध और मजबूत हुये। अमेरिका की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रधान मंत्री ने भीषण समुद्री तूफान के समय बंगला देश के लोगों के साथ सहानु-भूति प्रकट करने के लिये ढाका की यात्रा की तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना के लिये बुलाई गई राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लिया। प्रधान मंत्री ने फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान यूनेस्को में भाषण दिया। उन्होंने जिनेवा में आई० एल० ओ० के वार्षिक सम्मेलन में भी भाषण दिया। नेपाल नरेश, भूटान नरेश, नीदरलैंड की महारानी, मैक्सिको, मालदीव, स्वापी, श्रीलंका, तंजानिया, इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति और फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष, इथोपिया के राध्याध्यक्ष तथा पोलैंड, यूगोस्लाविया, मोरोशस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, यमन लोकतांत्रिक गणराज्य एवं त्रिनिडाड व टोबगो के प्रधान मंत्री हमारे देश की राजकीय यात्रा पर आये। नावों के युवराज तथा राजकुमारी और पोप ने भी भारत की यात्रा की।

44. अब मैं वर्ष 1986-87 तथा उसके बाद के लिये कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा।

45. समय की मांग है कि गरीबी के रहन सहन के दर्जे को ऊंचा उठाया जाय। इस बुनियादी उद्देश्य की प्राप्ति में विज्ञान तथा टेक्नालाजी की सहायता लेनी होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार निम्न-लिखित क्षेत्रों में टेक्नालोजी मिशन स्थापित करेगी:—

(i) सभी गांवों में पीने का पानी ;

(ii) निरक्षरता दूर करना ;

(iii) बच्चों को टीके लगाना तथा उनका प्रतिरक्षण

(iv) तिलहनों तथा खाद्य तेलों का उत्पादन;

(v) विकसित संचार सुविधाएं।

46. इस वर्ष के दौरान उद्योग और कृषि की उत्पादकता में सुधार के लिये टेक्ना-

लोजी का प्रयोग करने के उद्देश्य से ऐसे क्षेत्रों की निर्धारित किया जाएगा। चुने हुये क्षेत्रों में विज्ञान और टेक्नोलोजी मिशनो भारत को वैज्ञानिक कार्य-कलापों की पहली पंक्ति में लाने की कोशिश करेंगे।

47. एक व्यापक कृषि नीति बनाई जाएगी जिससे कि साधनों का समुचित उपयोग हो सके, जल और मिट्टी की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, सभी फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जाए, छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि की जाए और तिलहन तथा दालों की पैदावार को बढ़ाकर अनाज के मामले में कड़ी मेहनत से हासिल की गई आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए। पूर्वी क्षेत्र में हरी क्रांति लाने के लिये एक समय बद्ध कार्य योजना तैयार की जाएगी।

48. यह संतोष की बात है कि जल को एक राष्ट्रीय संसाधन समझने पर राष्ट्रीय सहमति तैयार हुई है। सरकार राष्ट्रीय जल नीति के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है जिससे कृषि, उद्योग और दूसरी सामाजिक जरूरतों के लिये जल का अधिकतम उपयोग होगा।

49. सरकार ने हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रमों का गहन विश्लेषण किया है। पिछले अनुभवों का लाभ उठाते हुए परिवार नियोजन के लिये एक अधिक कारगर नीति तैयार की जा रही है जिसकी जल्दी ही घोषणा की जाएगी।

50. गरीबी दूर करने के कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों पर आधारित एक नया कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और उसकी घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी। इसमें बड़े पैमाने पर गरीबी के सभी पहलुओं, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर एक मुख्य प्रयास के रूप में सभी तत्वों, नीतियों और कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक

और सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों को जोर-शोर से लागू किया जाएगा। अल्प-संख्यकों के विकास के लिये 15 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने पर जिसमें आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ाये जाने पर खास जोर दिया गया है, पूरी नजर रखी जाएगी।

51. जनसामान्य को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास में गति लाने और भारतीय उद्योग की कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिये उद्योग नीति को एक व्यापक स्वरूप देने की आवश्यकता है। हमारी उद्योग नीति में पहले ही काफी परिवर्तन किये गये हैं, जो कि अब आधुनिकीकरण के नए आयाम, नयी तकनीकों के समावेश तथा देशी तकनीकों के विकास के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। ऊंची लागत और अकुशल उद्योगों से गरीबों को तकलीफ होती है क्योंकि ये उन साधनों को अपने में समा लेते हैं जो गरीबों को नए रोजगार दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। वस्तुओं के उत्पादन और आयात तथा शहरी क्षेत्रों के लिए सेवाओं में हर सम्भव वृद्धि करना गरीबों हटाने की हमारी नीति का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिये उत्पादन का पैमाना क्षमता उपयोग, स्वदेशी टेक्नोलोजी की भूमिका, श्रम उत्पादकता, विस्तृत नियंत्रक कार्यप्रणाली, भविष्य में लघु और मध्यम उद्योगों के महत्व और मौजूदा प्रशासनिक तथा प्रबन्ध-तंत्र का संचालन करने वाली नीतियों पर नए सिरे से विचार करना होगा। उद्योगों को चाहिए कि वे विशाल जन समुदाय की सेवा करें।

52. भूगतान शेषों को एक व्यावहारिक स्थिति बनाए रखने की चुनौती का सामना करने के लिए निर्यात और पर्यटन को बढ़ावा देने की भारी जरूरत है। इन क्षेत्रों की उन्नति में किसी तरह की असावधानी हमारी सम्पूर्ण विकास नीति को ही संकट में डाल देगी। सरकार इस अहम क्षेत्र में नई पहल करेगी।

63. हमारे प्रशासनिक ढाँचे में परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे कि सामाजिक न्याय के साथ विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके । सरकार में प्रबन्ध को नई सामाजिक विचार धारा के अनुरूप ढालना है । यह ऊपर से कुछ लादने का प्रश्न नहीं है । सुधार की भावना अन्दर से आनी चाहिए । सम्पूर्ण राष्ट्रीय समुदाय को प्रशासनिक कार्यप्रणाली से ताल्लुक रखने वाले मुद्दों पर बहुसंख्यक हिस्सा लेना चाहिए । इसी प्रकार एक ठोस कार्यक्रम सामने आएगा । हमारे प्रशासन में कार्यकुशलता और जिम्मेदारों की भावना आनी चाहिए ।

64. हमें अपनी बुनियादी राजनैतिक संस्थाओं की स्वस्थ और प्राणवान रखने के लिए अपने चुनाव सम्बन्धी तथा अन्य कानूनों को बदलने की जरूरत होगी । सरकार ठोस सुझावों के लिए राजनैतिक पार्टियों के नेताओं से विस्तार के साथ सलाह-मशविरा करेगी जिससे कि सार्वजनिक जीवन को और साफ-सुथरा बनाया जा सके ।

65. एक शक्तिशाली भारत की कल्पना सभी साकार होगी जबकि पुरुषों और महिलाओं के वास्तविक जीवन में चरित्र-बल, उद्देश्य के प्रति दृढ़ता और श्रेष्ठता के प्रति वचनबद्धता होगी । मानव संसाधनों के विकास के लिए सरकार की नीति का लक्ष्य हमारे राष्ट्रीय जीवन में इन गुणों का विकास करना है । नई शिक्षा नीति इस नीति का एक अभिन्न अंग होगी । इसका उद्देश्य सद्भावना-पूर्ण वातावरण में समाज का शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास करना होगा ।

66. केवल लक्ष्यों की बात करना काफी नहीं होगा । नई शिक्षा नीति को लागू करने में आवश्यक साधन मिलते रहें, इसके लिए राष्ट्रीय गतिशीलता आवश्यक है । इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में की जा रही राष्ट्रीय कोशिशों को एक नई दिशा देने में युवकों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, बुद्धिजीवियों, कामगारों तथा किसानों का योग-

दान होना चाहिए । अपने सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए हमें शिक्षा को कक्षाओं की सीमा से बाहर निकाल कर उसे एक सामाजिक प्रक्रिया का रूप देना होगा । हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और उसे समृद्ध बनाने के अपने दृढ़ निश्चय और उत्पादन, दोनों ही के साथ शिक्षा को और मजबूती के साथ जोड़ना होगा ताकि हम अपने भारतीय होने पर गर्व कर सकें ।

67. आने वाले वर्ष चुनौतियों के वर्ष हैं । सरकार ने विकास में तेजी लाने, अर्थ-व्यवस्था को आधुनिक बनाने और सामाजिक न्याय हासिल करने के अपने कार्यक्रमों को नया रूप देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं । यह जरूरी है कि इन्हें लागू करने के काम की अहमियत को समझाया जाए ।

68. पिछले वर्ष हमारी बहुत सी उलझाइयाँ रहीं । हमारी जनता को हमसे बड़ी आशाएं तथा आकांक्षाएं हैं । उनके प्रतिनिधि होने के नाते उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना आपका प्रमुख कर्तव्य है । इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे समाज को धर्मनिरपेक्ष और लोकतन्त्र की बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों और सभी राजनैतिक विचार-धाराओं के संगठनों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए । हिंसा और कट्टरता की तकतों के साथ लड़ना होगा । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने अपनी आर्थिक क्षमताओं को इतना मजबूत बना लिया है कि अब हम दृढ़ और सम्मिलित कोशिशों के जरिए आगे बढ़ सकते हैं और निर्धनता को दूर कर सकते हैं । अब समय आ गया है कि हम और अधिक राजनैतिक समरसता पैदा करें, जिससे कि निर्धनता और पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ाई जीता जा सके । आपके सामने जो कार्य करने को हैं, उनमें आपकी सफलता की मैं कामना करता हूँ ।

जय हिन्द !

**[Text of the President's
Address in English]**

HONOURABLE MEMBERS,

It gives me great pleasure to welcome you to this first session of Parliament in 1986. I felicitate the new members.

2. The year has seen Parliament transact its business in a purposeful manner and in an atmosphere of cooperation. I extend to you all my best wishes for the successful completion of the budgetary and legislative business that lies ahead.

3. In July, 1985, the Government took a major initiative to resolve the complex and difficult problems in Punjab. Our prime concern was to strengthen the forces of unity and integrity. Policy was governed by the perspective of serving the highest national interest. The democratic process triumphed over terrorism. The peaceful elections in Punjab testified to the desire of the overwhelming majority of the people for peace and normalcy in the State.

4. A great responsibility rests on those who have secured the mandate of the people. Their supreme task is to isolate those who are resorting to violence to disturb communal harmony and peace. In this task they will have the support of all political forces committed to the unity and integrity of India. There cannot be, and must not be, any compromise with the forces of disintegration. It is imperative that all secular and democratic forces join hands in a mass campaign to safeguard the values enshrined in our Constitution—nationalism, secularism, democracy and socialism—the bedrock of India's unity.

5. The Assam settlement was followed by elections to the Legislative Assembly and the Lok Sabha. A new Government has taken office.

6. Government are committed to the fullest implementation of the Punjab and Assam Accords.

7. Government express their deepest sympathy with the families of all those who lost their lives, or were injured, or suffered loss of property in violent incidents in different parts of the country. Violence in public life is the very antithesis of the ethos of our civilization. The frequent resort to violence to settle what are perceived as grievances, of one group or another should deeply disturb those who uphold democratic values. While governments must firmly put down violence wherever it may occur, it is essential that political parties committed to democratic values should deal with the root causes of violence through purposive and sustained work among the people. The temptation to seek short-term advantages from communal and other types of violence must be eschewed.

8. Communalism continues to pose a serious threat to national unity. It is being reinforced by religious fundamentalism and fanaticism. These trends represent a reactionary social outlook, directed against the struggle of the poor and the underprivileged against the vested interests. The reconstituted National Integration Council will have to act decisively and systematically to strengthen secularism.

9. In my Address on January 17, 1985, I had outlined the major policies and programmes of the Government. I recapitulate the main points:-

- (i) Commitment to a clean public life;
- (ii) Administrative reforms;
- (iii) Judicial reforms;
- (iv) A new national education policy;
- (v) A new national programme for women;
- (vi) Participation of youth in programmes for promoting

national integration and achieving excellence;

(vii) Establishment of a Wasteland Development Board;

(viii) Formation of a Central Ganga Authority;

(ix) A new textile policy; and

(x) Thorough examination of safety measures for industrial establishments.

10. My Government have fulfilled in substantial measure the tasks they had set for themselves for the past year.

11. The anti-defection Act is now on the statute book. Contributions to political parties by the companies have been permitted by law. Government have endeavoured to set a new tone in public life. This has strengthened national confidence. A strong sense of involvement in public affairs among all sections of the people and a buoyant spirit have characterised the year that has gone by. We have to build on these assets to raise the standards of public life.

12. Vigorous steps have been taken to combat corruption and to improve the performance of the public services. Strong emphasis has been laid on sound personnel management and training of personnel at all levels. Machinery for redressal of public grievances is in place. Its results are being continuously evaluated. A new Ministry has been set up to monitor the implementation of various programmes. All Departments of Government have been directed to formulate detailed action plans for the coming financial year, against which their progress will be judged. Administrative reforms is a continuous process. Detailed exercises are underway to reorient the system to speedier decision making and better implementation.

13. Government are determined to eliminate delays in dispensation of justice. The experiment of Lok Adalats has proved that an innovative approach is required to cure this malady. The establishment of Administrative Tribunals will also lighten the burden of the courts, enabling them to devote more time to the liquidation of arrears. However, these are just the first steps in tackling the basic problem of making justice inexpensive and easily accessible to the poor. Drastic changes are needed. Government have entrusted to the Law Commission the task of recommending such changes.

14. Government published in August, 1985, a status paper entitled "The Challenge of Education". This was intended to stimulate wide and intensive national debate on issues and alternatives. Government note with satisfaction that the debate has involved all sections of the people and many useful ideas and approaches have emerged. A draft of the new Education Policy will be presented shortly to Parliament.

15. Government have set up a new department to look after the development of women. A comprehensive national programme for women is being worked out. It will aim at enabling women to play their full part in developing a strong and modern nation.

16. Programmes for youth development have made considerable headway but such more has to be done in this area.

17. The Wasteland Development Board has been set up and has started work on an ambitious programme of afforestation. In a recent meeting, all the State Governments endorsed an integrated approach to a National Land Use Policy as well as the strategies and policies for wasteland development.

18. The Central Ganga Authority has come into existence. With the cooperation of the concerned State Governments, work has started in full swing on stopping the pollution of the Ganga.

19. A new textile policy was announced in June 1985. It aims at production of cheaper cloth for the people. An equally important objective of the policy is to protect the interests of handloom weavers. It is envisaged that in the Seventh Plan the entire production of 700 million sq. meter of controlled and janata cloth will be transferred to the handloom sector. The Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 has been passed to strengthen this vital sector which provides livelihood to millions. Steps are being taken to ensure full and efficient implementation of the policy.

20. Government have completed examination of issue relating to industrial safety and management of hazardous substances and legislation will be introduced in this session of Parliament.

21. Government will establish seven zonal cultural centres — three have already been set up — to promote a sense of cultural cohesion. These centres, cutting across territorial and linguistic boundaries, would project the rich diversity of regional, cultural traditions and their underlying unity. They would take the best of our culture to the masses, harmonising it with their lives and struggles. Their essential thrust would be to break the artificial barriers created during the colonial era between the masses and the living tradition of India's age-old culture in all its forms. The centres will also aim at revitalising folk art which has enriched the country's cultural life.

22. I would now refer to the major trends in our economy.

23. The Seventh Five Year Plan was approved by the National

Development Council. The basic strategy of the plan is cast in a longer term perspective of eradication of poverty and building a strong, self-reliant and modern economy. The Plan sharpens the focus on the anti-poverty programmes which will have an expanded coverage. It also envisages adequate investments in the core sectors to strengthen the growth potential of the national economy.

24. The fulfilment of the Plan requires total commitment and determination to mobilise adequate resources for investment. To translate the vision of a strong, prosperous, self-reliant India into reality requires unremitting toil and capacity to sacrifice and to bear hardship. Adequate savings have to be mobilised to pursue a non-inflationary path of development. More importantly, these savings have to be used effectively. The challenge has to be met. There are no short cuts to development, no alternatives to hard work.

25. Vigorous implementation of anti-poverty programmes yielded significant results. The Sixth Five Year Plan aimed at assisting 15 million families under the Integrated Rural Development Programme; 16.6 million families were actually covered, of which 6.4 million belonged to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. These programmes are being strengthened and surplus foodgrains stocks will be used in 1986-87 to expand the National Rural Employment Programme and the Rural Landless Employment Guarantee Programme to cover one million additional families. An amount of Rs. 100 crores has been provided annually during the Seventh Five Year Plan for the construction of housing for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and freed bonded labour.

26. By the end of March, 1985 of a total of 2.31 lakh problem villages lacking safe drinking water supply, 1.92 lakh villages had been provided with at least one source of water supply. During 1985-86 the programme was further accelerated.

27. In 1985-86, agriculture continued to make steady progress. In November, 1985, foodgrains stocks with Government were higher by nearly 15% over 1984. This has enabled Government to launch a scheme for distributing wheat and rice at specially subsidised rates in tribal areas and to other vulnerable sections, especially the Scheduled Castes, expectant mothers, children, etc. A comprehensive crop insurance scheme has been introduced in specified areas for the kharif crop. Government are considering further expansion of such schemes.

28. During the first seven months of 1985-86, industrial production grew at the rate of 6.3%. The policy initiatives of Government have created a buoyant investment climate. The infrastructural industries have performed well. Compared with the first nine months of the last year, power generation was up by 8.2%; saleable steel production by 12.9%; fertilizer production by more than 10%. Our ports handled 13.2% more cargo and the railways created an all time record in freight traffic movement.

29. In 1985-86 the Central Plan outlays were stepped up by 15% over 1984-85, specially on anti-poverty programmes, human resource development and infrastructure. There was considerable increase in the outlays of State Plans. Government will have spent in 1985-86 Rs. 1650 crores on food subsidy and Rs. 2050 crores on fertilizer subsidy. Public distribution system was strengthened and prudent management of supplies prevented shortages. It is gratifying that a significant increase in public investment was achieved.

30. Tax collections have been buoyant, belying gloomy forebodings. The collection of direct taxes is up by about 23% compared to the corresponding period last year. Indirect tax collection has increased by 22%. Total tax collections have increased by 22% which is the highest in the last decade. An effective drive was launched against tax evaders, smugglers and blackmarketeers. Action has also been taken against personnel found guilty of colluding with economic offenders. Government are determined to cleanse the economic life and to fight the evil of black money.

31. For the first time, a long term fiscal policy co-terminous with the Five Year Plan has been announced. A long-term direction to economic policy has been provided. Government are confident that the policy will ensure economic growth and speedier expansion of productive investment and employment opportunities.

32. It is necessary to focus attention on the structural problems of the economy to further our basic objectives of growth with social justice. India's development depends upon steadily rising levels of public investment. How are these investments to be financed? Massive investments made in the previous Plans must yield adequate returns. Costs of production have to be reduced. Every paisa of national savings has to be put to the most productive use. Otherwise it will be difficult to find real resources for the larger and larger investments required for maintaining the tempo of self-reliant growth, for enlarging our anti poverty programmes and for preserving our economic independence. Sooner or later sooner rather than later we have to face the realities of the situation. No one should be under the delusion that growth social justice price stability and self-reliance are achievable without efficiency, discipline and sharing of burdens. Contemporary history warns us of such pitfalls.

33. We must reduce the costs of our inputs and prices of final products and services. We cannot afford the luxury of pricing ourselves out of both the domestic and the export markets. A modern industrial society cannot rise on the basis of continuing low levels of productivity and high costs of production. New jobs cannot be created if existing enterprises incur losses year after year. Operational inefficiency increases the cost of production and is inevitably reflected in increased prices which are a burden on the people. It raises costs all round, reducing real investment.

34. The future of the planning process depends on our capacity to face up to difficult questions and to take hard decisions, decisions that may involve sacrifices but without which forward movement will not be possible. Growth is absolutely vital to raise the standards of living of the poor. Can we evade decisions that protect and strengthen this development process? Nations are built by generations that sacrifice for a better tomorrow.

35. The balance of payments position poses a similar challenge. Our exports have remained sluggish in 1985-86 but our imports have increased. The imports of petroleum products and edible oils are well above the limits the country can afford. The question basically is whether we want to stand on our own feet or not. If we do, there is no question that we have to curb the growth of consumption of petroleum products and we have to be self-sufficient in oilseeds. We also have to have a fresh look at our imports of capital goods. We do not want to shut out new technology because that will harm us, but we have to make sure that such technology meets the rigorous criteria of essentiality. External financial flows are needed but Government are determined that India is never at the mercy of foreign banks and institutions. Economic independence and self-reliance are central to our philosophy of development. We

shall pay whatever price is required to maintain our economic independence.

36. The primary objectives of our foreign policy continue to be the promotion of non-alignment, advocacy of peace and nuclear disarmament, enlarging the area of friendship and cooperation and building of a just world order.

37. We welcome the resumption of high level dialogue between the USSR AND USA. It is imperative to take urgent steps to bring about a freeze in the nuclear arms race and a comprehensive nuclear weapon test ban treaty. The Six-Nation initiative has called for these measures. The Delhi Declaration of January, 1985 has had a good impact on public opinion throughout the world. The leaders of the six countries are in touch with one another about further steps.

38. During the last one year the atmosphere in the sub-continent has distinctly improved. We have succeeded in making progress with our neighbours in many fields. But we remain concerned about the ethnic situation in Sri Lanka and Pakistan's continued pursuit of a nuclear weapon capability. We remain convinced that the situation in Sri Lanka can be settled only through political means; attempts to seek a military solution will fail and will only result in the loss of a large number of innocent lives.

39. The Government welcome the establishment of South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Launched in Dhaka in December, 1985. We expect that it will help strengthen forces of friendship and cooperation in our region.

40. The Government have made untiring efforts towards the resolution of the major areas of tension. At the Commonwealth Meeting in the Bahamas in October, in which the Prime Minister participated, our delegation played a leading role in the adoption of the Commonwealth Accord on South Africa. We continue

to demand comprehensive mandatory sanctions against the racist regime in South Africa. If the authorities there, and other Governments in a position to influence South Africa do not act in time, violence on large scale will become unavoidable.

41. The Prime Minister also attended the 40th anniversary of the United Nations. The Nassau Declaration on World Order, adopted by Commonwealth leaders, contained a strong plea for adherence to international norms and principles and the strengthening of the United Nations. Support for the United Nations system is one of the corner-stones of our foreign policy. We are concerned at the growing threat to the multilateral institutions and the increasing tendency to resort to unilateral action. Government support international efforts to combat international terrorism, while recognising the rights of people under colonial occupation to use all means to attain their just objectives.

42. The Government deplore the fact that the Palestinian people continue to be denied their inalienable rights, including the right to an independent homeland of their own. Until this basic problem is tackled, West Asia will not see a lasting peace.

43. The Prime Minister paid official visits to the USSR, Egypt, France, Algeria, the U.S.A., Bhutan, the UK, Cuba, the Netherlands, Vietnam, Japan, Oman and Maldives. Our traditionally close and friendly relations with the USSR have been further strengthened following the Prime Minister's discussions with Soviet leaders in Moscow. The visit to USA has significantly enlarged the content of our bilateral relations with the USA. The Prime Minister visited Dhaka to express our solidarity with the people of Bangladesh during the cyclone disaster and participated in the meeting of Heads of State and Government for launching the South Asian Association for Regional Cooperation. The Prime Minister addressed the UNESCO during his visit to France. He addressed the annual conference

of the I.L.O. in Geneva. We had the privilege to host visits by the Kings of Nepal and Bhutan the Queen of the Netherlands, the Presidents of Mexico, Maldives, SWAPO, Sri Lanka, Tanzania Indonesia and Pakistan the Chairman of PLO the Head of State of Ethiopia and the Prime Ministers of Poland, Yugoslavia, Mauritius, Britain, New Zealand, People's Democratic Republic of Yemen and Trinidad & Tobago. The Crown Prince and Princess of Norway and the Pope also visited India.

44. Let me now outline some priority areas for 1986-87 and beyond.

45. The need of the hour is to enable the poor to better their lives. Science and technology have to support this fundamental objective. To this end, Government are mounting technology missions in the following areas:—

- (i) Drinking water for all villages ;
- (ii) Eradication of illiteracy ;
- (iii) Vaccination and immunisation of children;
- (iv) Production of oilseeds and manufacture of edible oils;
- (v) Improved communications.

46. In the course of the year more thrust areas will be identified with the object of using technology for improving productivity in industry and agriculture. In selected areas science and technology missions will endeavour to place India in the front rank of scientific activity.

47. A comprehensive agriculture policy will be formulated to promote an optimal cropping pattern, to improve water and soil management to increase productivity of all crops to enhance the incomes of small and marginal farmers and to enlarge our hard-won self sufficiency in food grains through higher production of oilseeds and pulses. A time bound action plan will be drawn up to take the green revolution to the eastern region.

48. It is gratifying that a national consensus has emerged on treating water as a national resource. Government attach high priority to the evolution of a national water policy which would optimise the use of water for agricultural, industrial and other social needs.

49. Government have carried out an indepth analysis of our family planning programmes. Profiting from the experience of the past, a more effective strategy for family planning is being worked out and will be announced shortly.

50. The focus on anti poverty programmes will be sharpened. A new programme, which builds on the success achieved by the revised 20-Point Programme is being formulated and will be announced soon. It will bring together all the elements, policies and programmes for a major national effort to tackle the mass poverty in all its manifestation, specifically the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Programmes for the social economic, educational and cultural development for the Scheduled Castes, Tribes and other weaker sections will be vigorously implemented. The implementation of the 15-Point Programme for the development of minorities, with special emphasis on increasing economic opportunities will be closely monitored.

51. To rapidly increase employment, to stimulate development in backward areas and to enhance the efficiency of Indian industry to serve the masses better, a more comprehensive framework of industrial policy is required. Many changes have already been made in our industrial policy which now reflects the new thrust for modernisation absorption of new technologies and promotion of indigenous technologies. High cost and inefficient industry hurts the poor, because it absorbs resources that are needed to create new jobs for them. A vast increase in the production of goods and services for the masses in rural and urban areas is central to our strategy for the

removal of poverty. This necessitate a fresh look at policies governing scale of production, capacity utilisation, the role of indigenous technology labour productivity, the detailed regulatory mechanism, the future perspectives for small and medium industry and the existing administrative and management apparatus. Industry must serve the large masses.

52. To meet the challenge of maintaining a viable balance of payments position, a major thrust for promotion of exports and tourism is called for. Any slakening of progress on this front will jeopardise our overall development strategy. Government will take new initiatives in this critical areas.

53. It is imperative to effect changes in our administrative system to bring it in tune with the objective of growth with social justice. Management in Government has to be imbued with a new social outlook. It is not a question of imposing some thing from above. The impetus to reform must come from within. The national community as a whole must debate issues affecting the working of the administrative system. A concrete agenda of action will thus emerge for implementation. Our watchwords must be improvement of efficiency and enforcement of accountability.

54. To safeguard the health and vitality of our basic political institutions, changes will be needed in our electoral and other laws. Government will hold wide-ranging consultations with the leaders of political parties with a view to formulating concrete proposals to ensure cleaner public life.

55. The vision of a mighty India will be realised only in the actual lives of men and women who have strength of character, tenacity of purpose and commitment to excellence. Government's strategy for human resource development aims at developing these qualities in our national life. The new education policy will be an integral part of this strategy:

It will aim at the physical intellectual cultural and moral development of society in a harmonious fashion.

56. It is not enough to state objectives. A national mobilisation is essential to ensure that the resources required to implement the education policy are forthcoming. Even more important is the involvement of the youth students, teachers, the intelligentsia, workers and farmers in giving a new direction to the national effort in this area. Education has to be transformed from an activity in the classroom to a social process for building the India of our dreams. It has to be integrated more closely both with production and our commitment to conserve and enhance our cultural heritage to make us proud to be Indian.

57. The years ahead are years of challenge. Government have taken a number of measures to accelerate growth to modernise the economy and to give new content to our programmes for achieving social justice. It is imperative to impart a sense of urgency to the task of implementation.

58. Much has been achieved this past year, and the hopes and expectation of our people are high. As their representatives, you have the onerous duty to fulfil their aspirations. Above all, people's representatives and organisation of all political persuasions should work together to strengthen the secular and democratic foundations of our society. The forces of violence and fanaticism have to be fought. The economic capabilities we have built up since independence have brought us to a point where determined and concerted efforts to take us forward and to remove poverty are feasible. Now is the time to ensure greater political cohesion so that the battle against poverty and backwardness can be won. I wish you all success in the tasks ahead.

Jai Hind !

OBITUARY REFERENCES

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I refer with profound sorrow to the passing away of Shri R.T. Parthasarathy and Shri Maheswar Naik, former Members of the Rajya Sabha.

Shri R. T. Parthasarathy was born in Madras in February 1921 and got his education at Tirchirappalli and Madras. A grandson of the veteran freedom fighter and former President of the Indian National Congress, late salem Vijayaraghavachari, Shri Parthasarathy was a very dedicated social and political worker. Shri Parthasarathy was a lawyer by profession but he also made his mark as a keen sportsman, especially in cricket. In his younger days, he represented the erstwhile State of Madras in the Ranji Trophy Cricket Tournament and thereafter became a well known cricketed commentator on All India Radio. Shri Parthasarathy was a Member of the All India Council of Sports for some time. A person of amiable disposition Shri Parthasarathy was a forceful speaker and took active part in the debates during his term in this House from April 1966 to April 1972. In his passing way, the country has lost an active social worker and eminent sports personality.

Born at Mayurbhanj in Orissa in July, 1906 Shri Maheswar Naik was educated at Ravenshaw College, Cuttack and at the Patna University. In his early career, Shri Naik was in Government service in the erstwhile princely state of Mayurbhanj and served the state in various capacities. Shri Naik served as a Member of the Provisional Parliament from 1950 to 1952 and as a member of this House from 1956 to 1962. Shri Naik worked for the upliftment of the weaker sections of the society and the welfare of woman and the backward classes, with special emphasis on their educational and economic advancement. He started several educational institutions, welfare centres and villages libraries. During his tenure as a Member of this House, he took keen interest in the proceedings..